एस. एस. संधावालिया और जे. एम . टंडन समक्ष, जे जे

कृष्णकुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

विविध आपराधिक 1997 का क्रमांक 5500 – एम

7 अप्रैल 1978

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 11) - धारा 2 (एच), 93, 165, 166, 397(2) और 482 - संज्ञेय अपराध की जांच - ऐसी जांच के दौरान वारंट के अनुसार तलाशी और जब्ती - जाँच-पड़ताल की सहायता के लिए कदम - निष्पादित खोज वारंट क्या अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में रद्द किया जा सकता है – वारंट जारी करना; धारा 93 के तहत - क्या कोई अंतर्वर्ती आदेश है ताकि धारा 397(2) के प्रतिबंध को आकर्षित किया जा सके – मजिस्ट्रेट - तलाशी वारंट जारी करते समय उसकी संतुष्टि के लिए कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है या नहीं।

निर्धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट प्राप्त करना पुलिस की जांच शक्तियों की सहायता में एक कदम से ज्यादा कुछ नहीं है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों और न्यायक्षेत्रों के संबंध में उस पुलिस स्टेशन से परे जहां मामला दर्ज किया गया है। इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि पंजीकरण के अनुसरण में एक तलाशी या जब्ती संज्ञेय मामला चाहे धारा 93 के तहत मजिस्ट्रियल मंजूरी की सहायता से हो या उसके डेहॉर्स संहिता की धारा 165 और 166 आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत, स्पष्ट्रूप से साक्ष्य संकलन के लिए एक कार्यवाही है और इसलिए स्पष्ट रूप से संहिता के अंतर्गत जांच के दायरे में है। इस प्रकार संहिता की धारा 93 के तहत एक तलाशी वारंट एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त किया गया और उसके तहत की गई बाद की खोजे और जब्ती मामले की जांच के लिए बहुत अभिन्न अंग है की उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या प्रारंभिक चरण में ही रद्द कर दिया जाए जब मामला मुकद्दमे के लिए अदालत के समक्ष भी न रखा गया हो।

(पैरा 15 एवं 20)

जहां वारंट द्वारा अधिकृत तलाशी पहले ही पूरी हो चुकी है और संबंधित व्यक्तियों से संपत्ति की जब्ती विधिवत की गई है, तो केवल नियमितता ही नहीं, बल्कि तलाशी की अवैधता भी किसी भी तरह से संपत्ति और उसके तहत बनाई गई वस्तुओं की जब्ती को खराब या गैर-स्थायी नहीं बनाती है। उच्चतम स्तर पर किसी तलाशी की अवैधता या अन्यथा, चाहे वह वारंट के साथ हो या उसके बिना, अवैध खोज का विरोध करने के अधिकार से जुड़ा मामला होगा या अधिक से अधिक मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही में संलग्न किए जाने वाले सबूतों के महत्व से संबंधित होगा ऐसा हो सकता है। तलाशी वारंट की अवैधता अपने आप में उसके तहत होनेवाली कार्यवाही या उसके बाद हुई माल की जब्ती को पूरी तरह से अमान्य नहीं कर देगी।

इस प्रकार एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त संहिता की धारा 93 के तहत एक तलाशी वारंट, जिसे विधिवत निष्पादित किया गया और वापस कर दिया गया, समाप्त हो गया है और चीजों की प्रकृति के कारण तलाशी को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी तलाशी और जब्ती के तहत जब्ती को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका व्यर्थ और वस्तुतः निरर्थक है।

(पैरा 21 और 24)

यह निर्धारित किया गया कि तलाशी वारंट जारी करना एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान केवल एक कदम है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, इसलिए, आदेश की प्रकृति को अंतर्वर्ती माना जाना चाहिए। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि कम से कम उनके खिलाफ पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार धारा 397 (2) के तहत वर्जित है और इसलिए तलाशी वारंट जारी करने के खिलाफ निर्देशित समान या समान शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर अदालत की अंतर्निहित शक्तियों के तहत नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 27)

यह निर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 93 को केवल उस धारा की आवश्यकताओं के संबंध में न्यायालय के उचित विश्वास की आवश्यकता है। इसमें स्पष्ट रूप से या यहां तक कि निहितार्थ द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट अपने कारणों को विस्तार से दर्ज करने के लिए बाध्य है। संहिता स्वयं उन कारणों को दर्ज करने का प्रावधान करती है जहां विधायिका ने ऐसा निर्धारित करना उचित समझा है। इसलिए, जब विधानमंडल ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है, तो कारण दर्ज करने की आवश्यकता लागू करना अनुचित होगा। स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 93 के तहत कारणों को दर्ज करना कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में कोई कानूनी कमजोरी शामिल नहीं है।

(पैरा 34)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय ने 4 अक्टूबर 1977 के तलाशी वारंट को रद्द करने की कृपा की जो एफआईआर संख्या 106 में श्री बी. के. गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिवानी द्वारा, चौ. बंसीलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 201 के तहत 1 अगस्त 1977 को दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता के उस परिसर की तलाशी ली गई जिसके लिए उनके पास कोई वारंट नहीं था और जो समान बरामद किया गया था उसे वापस करने का आदेश दिया गया। 17 नवंबर 1978 को याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से के.एस. थापर, वकील, (दलीप सिंह और दीपक थापर, उनके साथ वकील)।

प्रतिवादियों की ओर से एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरवाना (नौबत सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता और एच. एस. गिल (उनके साथ सहायक महाधिवक्ता)।

कृष्णकुमार व हरियाणा राज्य (एस. एस. संधावालिया जे)

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, जे.-

(1) क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482, संहिता की धारा 93 के तहत जारी किए गए तलाशी वारंट (और अनिवार्य रूप से उसके अनुसरण में तलाशी और जब्ती) को रद्द करने का अधिकार देती है और विधिवत पंजीकृत संज्ञेय मामले की जांच के दौरान पहले ही निष्पादित हो चुकी है वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक संदर्भ पर हमारे सामने इन चार आपराधिक विविध अनुप्रयोगों में निर्धारण के लिए आता है।

(2) पक्षों के विद्वान वकील सहमत हैं कि तथ्य समान हैं, यदि समान नहीं हैं और यह निर्णय सभी चार मामलों को कवर करेगा। इसलिए, 1977 की आपराधिक विविध संख्या 5500 में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना पर्याप्त है।

(3) पहली अगस्त 1977 को चौ. बंसी लाल, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 161, 165ए तथा 201 के तहत पुलिस थाना सदर भिवानी में मामला दर्ज किया गया था। इसकी जांच के दौरान, श्री के.सी. कपूर, पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच एजेंसी, हरियाणा ने 4 अक्टूबर, 1977 को श्री बी.के. गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिवानीया के समक्ष (एक्जीबिट पी.1) व्यक्तियों के परिसर और उपरोक्त आवेदन से जुड़े अनुबंधों में निर्दिष्ट दस्तावेजों और रिकॉर्ड के संबंध में तलाशी वारंट जारी करने के लिए एक याचिका आवेदन दायर किया। इस आवेदन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जांच एजेंसी को उपलब्ध विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह विचार था कि जिन व्यक्तियों के कब्जे में और परिसर में ऐसे दस्तावेज, लेख, धन और संपत्तियों को छुपाया और गुप्त रखा गया था, यदि प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो उसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत न करें और इसके बजाय वे ऐसे सभी दस्तावेजों, संपत्तियों और वस्तुओं को नष्ट कर देंगे जो पंजीकृत मामले की सुचारू और उचित जांच के लिए हानिकारक होंगे। यह वादा किया गया था कि एक पखवाड़े के भीतर तलाशी वारंट अदालत को लौटा दिया जाएगा।

(4) उक्त आवेदन के समर्थन में राज्य के लोक अभियोजक को सुनने के बाद और उन्हें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश दर्ज किया

"वर्तमान: राज्य के लिए लोक अभियोजक।

सुनाया गया

याचिका के अनुसार तलाशी वारंट जारी किया जाए।

बी. के. गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रथम श्रेणी, भिवानी

4-10-1977

उपरोक्त वारंटों के अनुसरण में अगले दिन यानी 5 अक्टूबर, 1977 को पुलिस उपाधीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी ली गई और तीन गवाहों की उपस्थिति में 43 दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया, - अनुबंध पी-3 के अनुसार। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कब्जे के ज्ञापन की प्रति श्री तरलोक चंद के पुत्र श्री कृष्ण कुमार और श्री तरलोक चंद के पुत्र नरेश कुमार को दी गई थी, और जाहिर तौर पर उनके हस्ताक्षर उस पर लिए गए थे। तब वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी उक्त वारंट के निष्पादन के एक महीने और 12 दिनों के बाद न केवल तलाशी वारंट बल्कि उसके तहत की गई बाद की तलाशी और जब्ती को भी रद्द करने की मांग की गई।

(5) चूंकि इस प्रकृति की एक याचिका की स्थिरता ही कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1), मामले में की गई हालिया और स्पष्ट टिप्पणियों के मद्देनजर कुछ संदेह में प्रतीत होती है। मैंने विशेष रूप से इसकी योग्यता के तर्क पर, महाधिवक्ता, हरियाणा को प्रस्ताव का नोटिस देने का निर्देश दिया था।

(6) श्री के.सी. कपूर, पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच एजेंसी, हरियाणा की ओर से एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक ने विद्वान मजिस्ट्रेट को केस डायरी पेश की और संबंधित सामग्री के संबंध में याचिका पर बहस की और प्रकाश डाला, जिसके कारण तलाशी वारंट जारी करना जरूरी हो गया। इसके बाद ही विद्वान मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी करने के औचित्य के बारे में संतुष्ट होकर संहिता की धारा 93 के तहत विवादित आदेश पारित किया। फिर यह तर्क दिया गया कि उक्त तलाशी वारंट को न केवल विधिवत निष्पादित किया गया था और उसके तहत वसूली की गई थी, बल्कि उसके बाद 19 अक्टूबर, 1977 को संबंधित मजिस्ट्रेट को वापस कर दिया गया था। प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है याचिका अब निरर्थक है और सुनवाई योग्य नहीं है।

(7) जहां तक योग्यता का संबंध है, याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए कुछ तथ्यों का खंडन किया गया है और यह रुख अपनाया गया है कि तलाशी वारंट में किसी भी दोष के केवल दो कानूनी परिणाम हो सकते हैं, अर्थात् उसका विरोध करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके परिसर की तलाशी ली जानी है, या अधिक से अधिक न्यायालय को जब्ती के संबंध में साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए तैनात किया जाएगा। यह दावा है कि इन परिणामों के अलावा कोई और कानूनी परिणाम नहीं निकलता है और लेखों की तलाशी और जब्ती अप्रभावित रहती है। अंत में दृढ़ रुख यह है कि मामला अभी जांच के चरण में है और किसी भी अदालत में दायर नहीं किया गया है, वर्तमान याचिका अक्षम है। सर्च वारंट के लिए आवेदन दायर करने और उसके बाद के निष्पादन के संबंध में दुर्भावना के सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है।

(8) इसमें शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, मामले को 28 नवंबर, 1977 के मेरे विस्तृत संदर्भ आदेश के तहत एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। इसके मद्देनजर, अन्य तीन मामले कानून के समान मुद्दों को उठाते हैं तथा तथ्यों का भी उल्लेख किया गया तथा एक साथ सुनवाई एवं निस्तारण किया जा रहा है,

(9) शुरुआत में ही मैं इस बात पर प्रकाश डाल सकता हूं कि वर्तमान मामले में जांच के दायरे को बढ़ाना उपयोगी नहीं होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से जिस चीज को सख्ती से चुनौती दी जा रही है, वह एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्राप्त संहिता की धारा 93 के तहत तलाशी वारंट हैं, जो विधिवत निष्पादित किया गया और बाद में, न्यायालय में वापस लौटा दिया गया। इसलिए, तलाशी वारंट के मामले जो पहले से ही निष्पादित नहीं किए गए हैं या जो संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान अन्यथा प्राप्त किए गए हैं, वे स्पष्ट रूप से एक अलग वर्ग बनाते हैं और उन पर अलग-अलग विचार लागू हो सकते हैं। इसलिए, मैं ईमानदारी से दूसरे वर्ग को अपने दायरे से बाहर कर दूंगा और खुद को उस विशिष्ट मुद्दे तक ही सीमित रखूंगा जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उठता है।

(10) प्रतिवादी राज्य की ओर से वर्तमान याचिका की स्थिरता के खिलाफ तीनतरफा तर्क किया गया है। पहला तर्क यह दिया गया है कि विधिवत पंजीकृत संज्ञेय मामले में उत्पन्न होने वाली संहिता की धारा 93 (और उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही) के तहत तलाशी वारंट प्राप्त करना और कुछ नहीं है बल्कि इसकी जांच के क्रम का चरण है। माना कि मौजूदा स्तर पर किसी भी अदालत में कोई चालान या अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इसलिए, यदि पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय मामले में जांच की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के तहत की गई तलाशी, या मजिस्ट्रेट से प्राप्त तलाशी वारंट की तरह एक कदम मात्र है। इस प्रारंभिक चरण में उसकी सहायता में समान रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है या उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

(11) दूसरी, चुनौती इस आधार पर आधारित है कि एक बार तलाशी वारंट, भले ही अमान्य हो, जारी और निष्पादित हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है, और चीजों की प्रकृति से प्रक्रिया को उलटा नहीं किया जा सकता है। किसी भी तथ्य या नियति को रद्द करने या खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता।

(12) चुनौती का तीसरा आधार पुराने और संबंधित प्रावधानों के प्रतिस्थापन में वर्तमान संहिता की धारा 397 द्वारा लाए गए आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून के हालिया संशोधन के अंतर्निहित सिद्धांत पर उठाया जाना है। विशेष रूप से धारा 397 की उप-धारा (2) पर जोर दिया गया है जो अब प्रावधान करती है कि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसी अपील, मुकदमे, जांच या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर यह तर्क दिया गया है कि तलाशी वारंट जारी करना या उससे इनकार करना एक अंतर्वर्ती प्रकृति का उच्चतम स्तर है और यदि स्पष्ट रूप से उसके संबंध में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को वर्जित कर दिया गया है, तो उक्त प्रावधान को दरकिनार करके संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों की आड़ में समान क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके समान परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(13) वर्तमान याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाने वाले उत्तरदाताओं की ओर से पहले विवाद की ओर इशारा करते समय, जो सवाल उठता है वह यह है कि सर्च वारंट और पुलिस द्वारा एक पंजीकृत संज्ञेय मामले की जांच के दौरान उसके तहत की गई जब्ती की प्रकृति और कानूनी चरित्र वास्तव में क्या है। मुद्दे की जड़ यह है कि क्या यह ऐसे मामले की जांच के दायरे में आता है? इसलिए, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (एच) का संदर्भ अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, जो निम्नलिखित शब्दों में जांच का वर्णन करता है:

"जांच में एक पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा (मजिस्ट्रेट के अलावा) जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत है, किए गए सबूतों के संग्रह के लिए इस संहिता के तहत सभी कार्यवाही शामिल हैं"।

इसी चरण में, संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना भी उपयुक्त है। अध्याय XII संज्ञेय या अन्यथा, अपराधों की जांच करने की पुलिस की शक्तियों से संबंधित है। मामलों के इन दो वर्गों की जांच के संबंध में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां संज्ञेय मामलों में स्टेशन हाउस अधिकारी को तुरंत अपराध की जांच करने का अधिकार है, वहीं गैर-संज्ञेय मामले में वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश ऐसा नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ऐसे मामले की सुनवाई करने या संहिता की धारा 155(2) के तहत मामले को सुनवाई के लिए सौंपने की शक्ति है। अब धारा 165 किसी संज्ञेय मामले की जांच कर रहे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भी चीज़ की खोज करने या तलाशी कराने का अधिकार देती है। वह या तो स्वयं ऐसा कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद तलाशी लेने के लिए कह सकता है। अनुवर्ती धारा 166 एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, चाहे वह उसी जिले में हो या किसी अन्य जिले में, किसी भी स्थान पर तलाशी लेने की आवश्यकता के लिए अधिकृत करती है, जहां पूर्व अधिकारी वह अपने ही स्टेशन की सीमा के भीतर ऐसी तलाशी करवा सकता है। इसके बाद इस प्रकार अधिकृत अधिकारी उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ सकता है जिसमें मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी संज्ञेय मामले (जिससे हम यहां मुख्य रूप से चिंतित हैं) के पंजीकरण पर, उसकी जांच करने वाला पुलिस अधिकारी पर्याप्त कारणों से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्वयं तलाशी ले सकता है या उसकी ओर से उसके अपने पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर और बाहर दोनों जगह किसी अन्य को ऐसा करने के लिए अधिकृत या अपेक्षित कर सकता है।

(14) धारा 93 के तहत तलाशी वारंट जारी करने को अधिकृत करने वाली संहिता का अध्याय VII चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसलिए, संज्ञेय अपराध की जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी के पास संहिता की धारा 165 और 166 के प्रावधानों का सहारा लेने या उसकी धारा 93 के तहत मजिस्ट्रेट की अतिरिक्त सहायता लेने का विकल्प होता है। अब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी संज्ञेय मामले की जांच के दौरान तलाशी या जब्ती, चाहे वह धारा 93 के तहत तलाशी वारंट की सहायता और मंजूरी के साथ की गई हो या धारा 165 और 166 के तहत इसके बिना की गई हो स्पष्टतः एक पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने की कार्यवाही है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से जांच के दायरे में है जैसा कि पहले उल्लिखित संहिता की धारा 2(एच) द्वारा परिभाषित या वर्णित है।

(15) इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 165 और 166 के तहत तलाशी या जब्ती स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा जांच के दायरे में आएगी। वास्तव में श्री थापर द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर गंभीरता से विवाद भी नहीं किया गया था। वास्तव में वकील यह स्वीकार करने के लिए काफी निष्पक्ष था कि संहिता की धारा 165 और 166 के तहत एक खोज स्पष्ट रूप से केवल उसी को रद्द करने के लिए संपार्श्विक हमले का विषय नहीं बन सकती है। यह स्वीकार किया गया कि ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसमें इस तरह की खोज को रद्द कर दिया गया हो। मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त करना मुझे पुलिस की जांच शक्तियों की सहायता के लिए एक कदम से अधिक कुछ नहीं लगता है और विशेष रूप से पुलिस स्टेशन से परे के क्षेत्रों और न्यायक्षेत्रों के संबंध में जहां मामला दर्ज किया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी संज्ञेय मामले के पंजीकरण के परिणामस्वरूप तलाशी या जब्ती, चाहे वह धारा 93 के तहत मजिस्ट्रेट की मंजूरी की सहायता से हो या संहिता की धारा 165 और 166 के तहत हो, स्पष्ट रूप से साक्ष्य संग्रह के लिए एक कार्यवाही है और, इसलिए, स्पष्ट रूप से संहिता के तहत एक जांच के दायरे में है। सिद्धांत रूप में, इसलिए, यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त धारा 93 के तहत वारंट के अनुसार तलाशी और जब्ती एक अभिन्न कदम के अलावा और कुछ नहीं है।

(16) हालाँकि यह मामला किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी यह अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों द्वारा समान रूप से समर्थित है। एच.एन. रिशबड और अन्य बनाम दिल्ली राज्य (2) में, उनका प्रभुत्व बिना किसी अनिश्चित शर्तों के इस प्रकार था:

"इस प्रकार, कोड जांच में आम तौर पर निम्नलिखित चरण होते हैं (1) घटनास्थल पर आगे बढ़ना, (2) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना, (3) संदिग्ध अपराधी की खोज और गिरफ्तारी, (4), अपराध के घटित होने से संबंधित साक्ष्यों का संग्रहण, जिसमें शामिल हो सकते हैं (ए) विभिन्न व्यक्तियों (अभियुक्तों सहित) की जांच करना और यदि अधिकारी उचित समझे तो उनके बयानों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, (बी) जांच के लिए और मुकदमे में पेश किए जाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों की तलाशी या चीजों की जब्ती, और..."

उनके आधिपत्य ने उपरोक्त निर्णय में यह भी कहा कि ऊपर बताई गई चीजें जांच के चरण थे और एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के लिए कुछ चरणों के लिए कुछ अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करना स्वीकार्य था। उपरोक्त दृष्टिकोण मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुबारक अली (3) में उनके आधिपत्य द्वारा उद्धृत और दोहराया गया था, और उसके बाद से विचलित नहीं हुआ है।

(17) एक बार जब यह माना जाता है कि धारा 93 के तहत किसी संज्ञेय मामले की जांच के दौरान तलाशी और जब्ती एक अभिन्न कदम है और मामला स्पष्ट रूप से मिसाल के दायरे में आता है कि ऐसी जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है या मामला अंततः न्यायालय में आने तक रद्द कर दिया जाए। चूँकि यह मुद्दा मुझे पूरी तरह से प्राधिकार द्वारा कवर किया गया प्रतीत होता है, इसलिए इसे विस्तार से बताना अनावश्यक है क्योंकि यह जाहिर है कि यदि पूरी जांच सुरक्षित है तो उस दौरान उठाए गए व्यक्तिगत कदमों या उन्हें रद्द करने के लिए संपार्श्विक हमले के माध्यम से जांच की अंतिम कार्रवाइयों को चुनौती देना हास्यास्पद होगा।

(18) तर्क को सीधे कवर करने वाला लोकस क्लासिकस सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद (4) है, और लॉर्ड पोर्टर के निम्नलिखित अक्सर उद्धृत शब्दों को याद किया जा सकता है:

"हालाँकि, उनके आधिपत्य की राय में, मामले का अधिक गंभीर पहलू पुलिस के कर्तव्यों के साथ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप में पाया जाना है। जिस तरह यह आवश्यक है कि अपराध के प्रत्येक आरोपी को ऐसा करना चाहिए न्याय के न्यायालय तक निःशुल्क पहुंच हो ताकि जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया है, उसके लिए दोषी न पाए जाने पर उसे विधिवत बरी किया जा सके, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका को उन मामलों में पुलिस के साथ उनके प्रांत के भीतर और जहां कानून उन पर जांच का कर्तव्य लगाता है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में जैसा कि दिखाया गया है, न्यायिक अधिकारियों से किसी भी अधिकार की आवश्यकता के बिना कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की जांच करने का पुलिस का एक वैधानिक अधिकार है। और, जैसा कि उनका कहना है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होना संभव है यदि इसमें न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के अभ्यास द्वारा उन वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो। न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, न कि अतिरेक और कानून और व्यवस्था के उचित पालन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक संयोजन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक को अपना कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए हमेशा, निशित रूप से सीआरपीसी की धारा 491 के तहत स्थानांतरित होने पर उचित मामले में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में निर्देश देने के आधीन है । हालाँकि, वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय के कार्य तब शुरू होते हैं जब कोई आरोप उसके सामने रखा जाता है, तब तक नहीं। कभी-कभी यह सोचा जाता है कि धारा 561-ए ने न्यायालय को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी हैं जो उस धारा के अधिनियमित होने से पहले उसके पास नहीं थीं, लेकिन ऐसा नहीं है।"

(19) पूर्वोक्त दृष्टिकोण को पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एस.एन. बसाक (5) के प्रसिद्ध मामले में उनके आधिपत्य की स्पष्ट पुष्टि प्राप्त हुई। बसाक के मामले में नियम को हजारी लाल गुप्ता बनाम रामेश्वर प्रसाद और अन्य (6) में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ फिर से पुष्टि की गई है:

"जहां फिर, किसी कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत की जाती है, उच्च न्यायालय ऐसी जांच में हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि यह तब जांच में बाधा उत्पन्न करेगा और वैधानिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार शक्ति का प्रयोग करेगा।"

जहान सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन (7) में, उनके आधिपत्य ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा, फिर भी जांच के दौरान अक्षम और समय से पहले होने के कारण उनकी बर्खास्तगी का निर्देश दिया। अंत में चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1 सुप्रा, समान रूप से स्पष्ट था) में न्यायालय के लिए बोल रहे थे:

“यह हमें अत्यधिक आश्चर्यचकित करता है कि उच्च न्यायालय ने सोचा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में, यह प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर सकता है। पुलिस ने विश्वविद्यालय के वार्डन द्वारा दायर शिकायत की जांच भी शुरू नही की है और एफ.आई.आर. के अनुसरण में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। यह महसूस किया जाना चाहिए कि अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को सनक या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। उस वैधानिक शक्ति का प्रयोग कम से कम, सावधानी से और दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए।“

(20) प्राधिकरण के उपरोक्त अतिरिक्त प्रभाव के प्रकाश में, मुझे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त संहिता की धारा 93 के तहत एक तलाशी वारंट और उसके तहत की गई बाद की तलाशी और जब्ती इस प्रकार जांच के अभिन्न अंग हैं कि इस प्रारंभिक चरण में उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है या उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है जब मामला अभी तक सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष नहीं है।

(21) अब उत्तरदाताओं की ओर से तर्क के दूसरे आधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्राथमिक ध्यान इस तथ्य पर है कि विवादित तलाशी वारंट को न केवल विधिवत निष्पादित किया गया है, बल्कि 19 अक्टूबर, 1977 को अदालत में वापस कर दिया गया है। वर्तमान आवेदन, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वारंट जारी होने के एक महीने और 12 दिन बाद और इसके निष्पादन और अदालत में वापस आने के लगभग एक महीने बाद दायर किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वारंट द्वारा अधिकृत तलाशी पहले ही पूरी हो चुकी है और संबंधित व्यक्तियों से संपत्ति की जब्ती विधिवत की जा चुकी है। एक बार ऐसा होने पर, इस प्रस्ताव के लिए उच्च अधिकार प्रतीत होता है कि केवल अनियमितता ही नहीं बल्कि तलाशी की अवैधता भी किसी भी तरह से संपत्ति और उसके तहत बनाई गई वस्तुओं की जब्ती को खराब या गैर-निष्पादित नहीं करती है। अधिकतम स्तर पर किसी तलाशी की अवैधता या अन्यथा, चाहे वह वारंट के साथ हो या उसके बिना, अवैध तलाशी का विरोध करने के अधिकार से संबंधित मामला होगा या अधिक से अधिक यह मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही में संलग्न किए जाने वाले सबूतों के महत्व से संबंधित हो ऐसा हो सकता है। किसी तलाशी वारंट की अवैधता उसके तहत होने वाली कार्यवाही या उसके बाद हुई माल की जब्ती को पूरी तरह से अमान्य नहीं कर देगी। राधा किशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (8) में, इस पहलू पर उनके प्रभुत्व ने निम्नानुसार अनिश्चित शब्दों में देखा है:

“हम पहले अंतिम चार बिंदुओं से निपटेंगे। जहां तक खोज की कथित अवैधता का सवाल है तो यह कहना पर्याप्त है कि यह मानते हुए भी कि तलाशी अवैध थी, वस्तुओं की जब्ती ख़राब नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 103 और 165 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा तलाशी का विरोध किया जा सकता है जिसके परिसर की तलाशी ली जानी है। यह भी हो सकता है कि तलाशी की अवैधता के कारण न्यायालय जब्ती से संबंधित साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए इच्छुक हो। लेकिन इन दो परिणामों के अलावा कोई और परिणाम नहीं निकलता।“

अब यह याद रखने योग्य है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ पुरानी संहिता की धारा 103 और 165 के उल्लंघन में एक अवैध खोज के संदर्भ में की गई थीं। यह स्पष्ट उल्लेख के योग्य है कि पुरानी संहिता की धारा 165, जो कि वर्तमान के प्रावधानों के साथ काफी हद तक समान है, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या संज्ञेय अपराध में जांच करने वाले एक अधिकारी को या तो स्वयं तलाशी लेने के लिए अधिकृत करती है या इसे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा करने का कारण बनाएं। यह स्पष्ट है कि किसी संज्ञेय

अपराध की जांच के दौरान तलाशी की यह शक्ति स्वयं पुलिस अधिकारी में निहित है और यह किसी भी न्यायिक मंजूरी या प्राधिकरण से स्वतंत्र है। इसी प्रकार पुरानी संहिता की धारा 103 में ऐसी तलाशी के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे। अब यदि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पेटेंट उल्लंघन और उनकी परिणामी अवैधता वास्तविक खोज और जब्ती को पूरी तरह से खराब नहीं करेगी, तो यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि धारा 93 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के तहत की गई खोज और जब्ती कम से कम एक समान और वास्तव में उच्चतर स्तर पर होगी। यदि एक पुलिस अधिकारी की अवैध कार्रवाई भी उसके द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को विफल नहीं करती है, तो यह स्पष्ट रूप से सबसे कम होगा, जहां एक समान खोज और जब्ती न्यायिक प्राधिकरण की मंजूरी के साथ की जाती है, भले ही अनियमित रूप से की गई हो। इसलिए, इन परिस्थितियों में धारा 93 के तहत तलाशी वारंट को रद्द करना या खारिज करना, जहां इसे पहले ही निष्पादित किया जा चुका है, निरर्थक अभ्यास की प्रकृति में होगा यदि इसके तहत की गई तलाशी और जब्ती अनिवार्य रूप से काफी हद तक अप्रभावित रहेगी।

(22) यह दोहराने योग्य है कि श्री थापर को वस्तुतः यह स्वीकार करना पड़ा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 या धारा 166 के तहत की गई कथित अवैध तलाशी को रद्द करने के लिए कोई भी याचिका कम से कम जांच चरण के दौरान सक्षम नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनेक मामलों में कानून संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान संहिता की धारा 165 या धारा 166 के तहत तलाशी को रद्द करने की मांग करने वाली मिसाल की कोई खोज नहीं कर सका। यदि स्थिति यही है, तो यह और भी अधिक असंभावित प्रतीत होता है कि एक समान खोज को रद्द करने की कार्यवाही केवल इसलिए होगी क्योंकि एक जांच अधिकारी ने समान परिस्थितियों में खोज करने के लिए न्यायिक आदेश की शुचिता की मांग की थी जो वह संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत स्वयं अच्छी तरह से कर सकता था। मेरे विचार से, संहिता की धारा 93 के तहत न्यायिक अंतर-स्थिति जांच अधिकारी की कार्रवाई को कमजोर करने के बजाय केवल शुचित ही कर सकती है। यह रेखांकित करने योग्य है कि वर्तमान मामले में हम केवल उस अपराध की जांच के दौरान तलाशी वारंट जारी करने से चिंतित हैं जो स्वीकार्य रूप से संज्ञेय है। यदि ऐसी अवैध तलाशी या जब्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है तो संहिता की धारा 93 के तहत मजिस्ट्रेट की न्यायिक मंजूरी के साथ की गई तलाशी के मामले में यह और भी अधिक होगा।

(23) अब तर्क के अलावा, इस प्रस्ताव के लिए उच्च अधिकार प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 93 के तहत शक्ति, एक बार प्रयोग और विधिवत अनुपालन के बाद प्रभावी न्यायिक समीक्षा से परे हो जाती है और उलटने में असमर्थ है। इंडियन एक्सप्रेस में मद्रास उच्च न्यायालय की एक बैठक (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (9), के पास इस प्रकार निरीक्षण करने का अवसर था:

“पहले प्रतिवादी ने श्री चरणजीव लाल से शपथ लेकर पूछताछ की थी और केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि मांगे गए दस्तावेज़ जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और जैसा कि श्री चरणजीव लाल ने दावा किया था, कंपनी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, विद्वान मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने प्रश्न पर अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करते हुए तलाशी वारंट जारी किया। विद्वान मजिस्ट्रेट अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं थे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के लिए आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट के पास विश्वास का कारण होना चाहिए कि मामलों की स्थिति ऐसी है या, दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि तलाशी वारंट जारी करने की आवश्यकता है, अन्यथा बात नहीं बनेगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक

पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी करने का अनुरोध करने की शक्ति देती है यदि उसके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि उस अपराध की जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसी तलाशी आवश्यक थी, जिसकी जांच करने के लिए वह अधिकृत है और श्री चरणजीव लाल, जिन्होंने तलाशी वारंट के लिए आवेदन किया था, ने विद्वान मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को उन आवश्यक सामग्रियों से अवगत कराया, जिनके आधार पर तलाशी वारंट की आवश्यकता थी और मजिस्ट्रेट इस तरह के वारंट की आवश्यकता से संतुष्ट थे और फिर इसे जारी किया। ऐसा होने पर तलाशी वारंट जारी करने में मजिस्ट्रेट का कार्य संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं होगा। इसके अलावा, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश रामप्रसाद राव ने बताया, तलाशी वारंट पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं। वारंट जारी करने को रद्द करने के लिए याचिका जारी करना अब व्यर्थ होगा। इसलिए, हमें 7 जून 1971 के सर्च वारंट को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करने का कोई आधार नहीं दिखता।“

अब यह याद रखने योग्य है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ भारत के संविधान के असंशोधित अनुच्छेद 226 के संदर्भ में की गई थीं। इसमें उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों का दायरा सबसे व्यापक था क्योंकि इसने इसे अनुच्छेद में निर्दिष्ट रिट की श्रेणी के अलावा 'किसी अन्य उद्देश्य के लिए' रिट जारी करने के लिए अधिकृत किया था और अन्यथा ब्रिटिश न्यायशास्त्र के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। अब यदि असंशोधित अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्तियों को भी सर्च वारंट को रद्द करने और किसी भी तरह से यह निर्धारित करने से रोक दिया गया था कि वास्तव में यह क्या था, तो यह बेहद असंभावित लगता है कि इस तरह के किसी भी परिणाम को आपराधिक प्रक्रिया धारा 482 के तहत अंतर्निहित सीमित शक्तियों के दायरा का सहारा लेकर प्रभावित किया जा सकता है।

(24) इसलिए, मैं यह मानूंगा कि संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त कोड की धारा 93 के तहत एक तलाशी वारंट, जिसे विधिवत निष्पादित किया गया है और वापस कर दिया गया है, समाप्त हो गया है और चीजों की प्रकृति के कारण उसके तहत तलाशी और जब्ती को उलटाया नही जा सकता है। इसलिए, ऐसी तलाशी और जब्ती को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका प्रकृति में निरर्थक और वस्तुतः निरर्थक है।

(25) अब उत्तरदाताओं की ओर से लगाए गए तर्क के तीसरे आधार पर आते हुए, यह मुद्दा संहिता की धारा 397 की उप-धारा (2) के हालिया प्रावधान के मद्देनजर स्पष्ट रूप से उठता है जो निम्नलिखित शर्तों में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को सीमित करते हैं: -

“397 (2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसी अपील, जांच परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।“

(26) अब कानून में इस संशोधन का प्रयोजन और उद्देश्य शायद ही संदेह में हो। विधि आयोग की प्रासंगिक रिपोर्ट के संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्पष्ट रूप से किसी मुकदमे, पूछताछ, जांच या अन्य कार्यवाही के दौरान वार्ताकार आदेशों पर सभी संपार्श्विक हमलों को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अनुभव से पता चला है कि वास्तविक व्यवहार में अंतरिम आदेश के संबंध में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग से आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे अत्यधिक देरी हुई है। वास्तव में कभी-कभी पुनरीक्षण उपाय बीमारी से भी बदतर हो जाता है, इसलिए विधायिका ने जानबूझकर अंतरिम आदेशों को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार से परे रखा है, जो इस संशोधन से पहले समान रूप से उसी में शामिल थे। यहां तक कि श्री थापर ने भी काफी

हद तक स्वीकार किया था कि जहां विधायिका ने किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्षेत्राधिकार पर रोक लगाने का विकल्प चुना है, वहां यह शायद ही न्यायालय के लिए खुला होगा और किसी भी मामले में अंतर्निहित शक्तियों की आड़ में ऐसी रोक को रद्द करना या बायपास करना उपयुक्त नहीं होगा। यह लंबे समय से स्थापित है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता उन मामलों के संबंध में व्यापक है जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है और अंतर्निहित शक्तियों का दायरा स्वचालित रूप से इसमें से बाहर रखा गया है।

(27) इसलिए, यह मुद्दा तुरंत उठता है कि क्या संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान संहिता की धारा 93 के तहत तलाशी वारंट जारी करना एक आदेश नहीं है जो अनिवार्य रूप से प्रकृति में अंतर्वर्ती है। अब यह स्पष्ट है कि यदि यह इस गुणवत्ता का हिस्सा है तो कम से कम संहिता के तहत न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वर्जित है और उपचार का सहारा केवल जांच, परीक्षण, जांच या अन्य कार्यवाही के निष्कर्ष पर ही लिया जा सकता है। पहले एक विस्तृत चर्चा के बाद यह माना गया था कि इस विशेष संदर्भ में तलाशी वारंट जारी करना एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान केवल एक कदम है और यह अनिवार्य रूप से पालन करेगा, इसलिए आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का माना जाना चाहिए । अमरनाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (10) में उनके आधिपत्य के निम्नलिखित अवलोकन सादृश्य द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे:

" इस प्रकार, उदाहरण के लिए, गवाहों को बुलाने का आदेश, मामलों को स्थगित करना, जमानत के लिए आदेश पारित करना, रिपोर्ट मांगना और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंतरिम आदेश के समान हो सकता है जिसके खिलाफ संहिता 1973 की धारा 397 के तहत कोई पुनरीक्षण नही होगा।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तलाशी वारंटों पर आमतौर पर अदालत के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हमला किया गया है, और वास्तव में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मामले, जिनका संदर्भ इसके बाद दिया जाएगा, स्वयं संकेत देंगे कि न्यायालय को प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में तलाशी वारंट हमले का विषय रहे हैं। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि कम से कम उनके विरुद्ध पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार धारा 397(2) के तहत वर्जित है। इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के रुख में पर्याप्त सामग्री है कि सर्च वारंट जारी करने के खिलाफ निर्देशित समान या समान शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत नहीं किया जाना चाहिए। यह पहलू के एक स्तर पर अमरनाथ के मामले में उनके आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था, (उपरोक्त):

"धारा 397 और 482 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से यह अनूठा निष्कर्ष निकलेगा कि जहां एक विशेष आदेश धारा 397(2) के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण का विषय नहीं हो सकता है, तो ऐसे मामले में प्रावधान धारा 482 का प्रयोग नहीं होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर तब किया जा सकता है जब विषय-वस्तु पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जहां कोई स्पष्ट प्रावधान है, किसी विशेष उपाय को छोड़कर, न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का सहारा नहीं ले सकता है।"

हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र स्टेट, (11) में उनके आधिपत्य के बाद के फैसले से उपरोक्त नियम की सख्ती और कठोरता कम हो गई है।

उंटवालिया जे ने पूर्वोक्त नियम के भाग को संशोधित करते हुए, न्यायालय की ओर से बोलते हुए यह कहना था:

कृष्णकुमार व हरियाणा राज्य (एस. एस. संधावालिया जे)

"लेकिन फिर यदि विवादित आदेश पूरी तरह से अंतर्वर्ती प्रकृति का है, जिसे 1898 संहिता के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इंकार कर देगा। लेकिन यदि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति लाता है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना नितांत आवश्यक है, तो धारा 397(2) में निहित उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित करना या प्रभावित करना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले इक्का-दुक्का ही होंगे. उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित ढंग से करना चाहिए।"

उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में, इसलिए, अब यह जांचने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या विवादित अंतरिम आदेश न्यायालय की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग में से एक है और क्या वर्तमान मामला उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां अंतर्निहित धारा 397(2) द्वारा बनाई गई रोक को खत्म करने के लिए न्यायालय की शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। शुरुआत में ही कहा जा सकता है कि मौजूदा मामले में ऐसा मानना दूर-दूर तक संभव नहीं है।

(28) अब सर्च वारंट जारी करने के खिलाफ श्री थापर द्वारा उठाए गए तर्क का मुख्य आधार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक दिमाग का कथित गैर-प्रयोग था। यह तर्क दिया गया कि आदेश मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखे बिना ही यांत्रिक रूप से दिया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों और परिसरों के संबंध में जारी किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि बाद में वारंट को इसके निष्पादन के लिए कई अन्य पुलिस अधिकारियों को समर्थन दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 80 थी।

(29) मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया स्टार तर्क भी अंततः बहुत ही नम्र व्यंग्य निकला है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर स्पष्टता से कहा था कि तलाशी वारंट के दायरे में आने वाले कुछ परिसर नई दिल्ली और यहां तक कि कलकत्ता में स्थित थे और यह संकेत देता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे जारी करने से पहले अपने दिमाग का दूर-दूर तक उपयोग नहीं किया था। यह तर्क स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य से रहित है। संहिता की धारा 93 का संदर्भ मात्र यह संकेत देगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के तहत तलाशी वारंट जारी करना बिना किसी क्षेत्रीय सीमा के है और विशेष मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। स्थिति मिसाल से भी समान रूप से स्पष्ट है। कानून और केस कानून की स्पष्ट भाषा का सामना करते हुए, श्री थापर को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि मजिस्ट्रेट देश के भीतर किसी भी स्थान के लिए वारंट जारी करने का हकदार था और उसके ऐसा करने का तथ्य एक ऐसा मामला था जो संभवतः उसके आदेश में थोड़ी सी भी निष्शक्तता नहीं ला सकता था।

(30) दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता यह तर्क देने में बहुत दृढ़ आधार पर थे कि यह दिखाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों साक्ष्य थे कि आदेश अभिलेखों के आधार पर और उस पर विचार के बाद पारित किया गया था। यह सही बताया गया था कि इसमें राज्य के लोक अभियोजक की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी गई थी और आगे विद्वान मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था कि उन्होंने याचिका के समर्थन में उनकी बात सुनी थी। यह सही तर्क दिया गया था कि न्यायिक आदेश में 'सुना' शब्द का एक सटीक अर्थ होता है और इस संदर्भ में इसके सामान्य शब्दकोश अर्थ पर भी भरोसा किया गया था। रैंडम हाउस डिक्शनरी में इस शब्द का प्रासंगिक अर्थ निम्नलिखित शब्दों में है:-

(5) "किसी चीज़ को औपचारिक, आधिकारिक या न्यायिक सुनवाई देना; आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश, संप्रभु, शिक्षक, सभा आदि के रूप में विचार करना; किसी मामले की सुनवाई करना। (6) (किसी के) साक्ष्य या गवाही के लिए लेना या सुनना : प्रतिवादी को सुनने के लिए।"

संक्षिप्त ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, निम्नलिखित अर्थ इस शब्द के लिए जिम्मेदार है: "

"(5) किसी न्यायालय में न्यायिक रूप से सुनना; (एक) सुनवाई देना; कोशिश करना (एक व्यक्ति या मामला); (6) शालीनता से सुनना; स्वीकार करना, अनुदान देना।"

इससे यह स्पष्ट है कि आंतरिक साक्ष्य याचिकाकर्ता के झूठे और निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले पर अपना दिमाग नहीं लगाया।

(31) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने ठीक ही बताया है कि न्यायालय के समक्ष किए गए आवेदन में, जिसे अवलोकन के लिए रखा गया था, स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या, जिन धाराओं के तहत इसे पंजीकृत किया गया था और आरोपी व्यक्ति और उसका पदनाम और स्थिति का उल्लेख किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला लोक अभियोजक द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में प्रस्तुत किया गया था, एक स्वाभाविक धारणा बनती है कि डायरियाँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई गई होंगी। हालाँकि, इस मुद्दे को केवल अनुमान या अनुमान तक भी नहीं छोड़ा गया है क्योंकि रिटर्न में इसे विशेष रूप से इस प्रकार बताया गया है -:
"यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि आवेदन के साथ पी. 1 दस्तावेजों और अन्य लेखों की सूची भी संलग्न की गई थी जिनके लिए खोज की जानी थी।
इसके बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने विद्वान मजिस्ट्रेट को केस डायरी दिखाई और खोज वारंट जारी करने की प्रासंगिक सामग्री पर प्रकाश डालते हुए मामले पर बहस की। इसके बाद ही विद्वान मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी करने के औचित्य के संबंध में संतुष्ट महसूस करने के बाद, याचिका के अनुलग्नक पी/2 के साथ आदेश पारित किया। यह तलाशी वारंट जारी करने में विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायिक दिमाग के प्रयोग के बारे में बहुत कुछ बताता है।"

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह दलील कि प्रासंगिक दस्तावेज़ों या रिकॉर्ड का विज्ञापन नहीं किया गया था, किसी भी तथ्यात्मक आधार पर आधारित नहीं है।

(32) कई अन्य पुलिस अधिकारियों को सर्च वारंट के बाद के समर्थन के संबंध में संहिता की धारा 74, 93 और 99 का संदर्भ दिया जा सकता है। धारा 74 में कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है, जिसका नाम उस अधिकारी द्वारा वारंट पर समर्थित है, जिसके लिए यह निर्देशित या समर्थित है। धारा 99 सहित अन्य में यह प्रावधान है कि धारा 74 के प्रावधान संहिता की धारा 93 के तहत जारी किए गए तलाशी वारंट पर लागू होते हैं। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदन के अनुलग्नक 'ए' में 86 व्यक्तियों और परिसरों का संदर्भ दिया गया है जिनके संबंध में तलाशी वारंट मांगा गया था। शपथ पत्र दिया गया कि सर्च वारंट एक पखवाड़े के भीतर वापस कर दिया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से ये तलाशी संभवतः किसी एक पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित नहीं की जा सकीं। यह ठीक ही बताया गया था कि तलाशी वारंट का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया होता यदि तलाशी शीघ्रता से और लगभग एक साथ नहीं की जाती ताकि सबूतों और उससे संबंधित दस्तावेजों को नष्ट होने या छिपाने से रोका न जा सके।

(33) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से खोज वारंट जारी करने में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मन का उपयोग न करने के संबंध में आरोप वर्तमान रिकॉर्ड पर निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया है।

(34) याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी करने के लिए अपनी संतुष्टि या उचित विश्वास को इंगित करने के लिए अपने विस्तृत कारण दर्ज नहीं किए थे और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है। मैं सैद्धांतिक रूप से इस विवाद की सराहना करने में असमर्थ हूं। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 93 को केवल उस धारा की आवश्यकताओं के संबंध में न्यायालय के उचित विश्वास की आवश्यकता है। यदि कहीं भी स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से यह प्रावधान नहीं है कि मजिस्ट्रेट अपने कारणों को विस्तार से दर्ज करने के लिए बाध्य है। यह याद रखने योग्य है कि संहिता स्वयं उन कारणों को दर्ज करने का प्रावधान करती है जहां विधायिका ने ऐसा निर्धारित करना उचित समझा है। इस संबंध में संहिता की धारा 116(3), 145(1), 165(1), 167(3), 203(1), 227, 239, 245, 256, 274 और 412 का संदर्भ लिया जा सकता है। इसलिए, जब विधायिका ने अपने विवेक से ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है, तो मिसाल के तौर पर कारण दर्ज करने की आवश्यकता थोपना मेरे विचार से अनुचित होगा। वास्तव में हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 93 को अन्य धाराओं के साथ मिलाकर पढ़ने से जो कारणों को दर्ज करने का प्रावधान करती हैं, अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है और मजिस्ट्रेट के उचित विश्वास के आधार पर रिकॉर्ड और उस पर उसके न्यायिक विवेक का प्रयोग ही कानून की आवश्यकता है। वास्तव में वह इस हद तक तर्क करने लगे कि तलाशी वारंट जारी करने के आदेश में बहुत विस्तृत कारणों की रिकॉर्डिंग, जो आवश्यक रूप से एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जांच के सभी चरणों और चीजों की प्रकृति और व्यक्तियों को तुरंत प्रकट कर देगी। जिन्हें बरामद करने की मांग की जा रही है, उसी चरण में जब जांच अभी भी गोपनीय और गुप्त प्रकृति की हो सकती है। मैं विद्वान महाधिवक्ता के तर्क के इस पहलू पर राय देने से बचूंगा लेकिन कम से कम इतना स्पष्ट है कि कारणों की रिकॉर्डिंग की अधिनियम की धारा 93 के तहत कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इसकी अनुपस्थिति में कोई कानूनी कमजोरी शामिल नहीं है।

(35) सिद्धांत और क़ानून के अलावा, माणिकलाल मंडल और अन्य बनाम राज्य (12) में डिवीजन बेंच के उच्च अधिकार की रिपोर्ट की गई है, इस प्रस्ताव के लिए कि तलाशी वारंट जारी करने में, एक मजिस्ट्रेट अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है और संहिता में केवल यह आवश्यक है कि वह स्वयं संतुष्ट हो कि इसे जारी करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को बाद में कनाईलाल जटिया और अन्य बनाम रामकृष्णदास गुप्ता, (13) में अपनाया गया है। कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, और अन्य बनाम सूरी और अन्य, (14) में डिवीजन बेंच ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। यहां तक कि श्री मेलिसियो फर्नांडीस बनाम श्री मोहन नायर और अन्य, (15) में विशेष बैंच, जिस पर श्री थापर ने भरोसा जताया है, ने शर्तों में देखा है कि मजिस्ट्रेट अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं था।

(36) संहिता की उन धाराओं के संदर्भ में जिनमें कारणों की रिकॉर्डिंग की भी आवश्यकता होती है, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्ताव के लिए उच्च अधिकार है कि वहां भी इसे रिकॉर्ड करने में विफलता से किसी भी तरह से कार्यवाही खराब नहीं होती है। अजायब सिंह और अन्य बनाम अमर सिंह और अन्य, (16) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि धारा 145(1) के अनुसार आदेश पारित करने में मजिस्ट्रेट की चूक एक इलाज योग्य अनियमितता है। इस संदर्भ में बाई राधा बनाम गुजरात राज्य (17) में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने इस प्रकार देखा है:

" हालाँकि, इस मामले में, यह देखा गया कि धारा 165 के तहत कारणों को दर्ज करने से अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता है, हालांकि ऐसा करने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। खोज करने का क्षेत्राधिकार या शक्ति क़ानून द्वारा प्रदान की गई थी और कारणों की रिकॉर्डिंग से प्राप्त नहीं हुई थी। ये अवलोकन दबाए गए पहले बिंदु को निपटाने के लिए पर्याप्त हैं जिसे खोज से पहले या उसके बाद भी उचित तरीके से कारणों को दर्ज करने की चूक के बारे में दबाया गया है।

इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि लिखित रूप में दर्ज किए गए विस्तृत कारणों की कथित अनुपस्थिति खोज वारंट जारी करने वाले आदेश की वैधता से किसी भी तरह से कम नहीं होती है।

(37) एक बार ऐसा हो जाने पर, यह स्पष्ट है कि किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी करने वाले आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा वास्तव में सीमित हो जाता है। यदि मामला प्राथमिक रूप से संबंधित मजिस्ट्रेट के उचित विश्वास और संतुष्टि से जुड़ा है और उसे कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है तो यह इस तथ्य की ओर एक स्पष्ट संकेतक है कि ऐसे विवेकाधीन आदेश को रद्द करने का सवाल आसानी से नहीं उठ सकता है।

(38) मामले के इस पहलू पर निष्कर्ष निकालने के लिए, मैं विवादित आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक कमजोरी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। यह एक न्यायिक आदेश होने के नाते वास्तव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने से बहुत दूर है, जो अनिवार्य रूप से प्रकृति में अंतर्वर्ती आदेश को रद्द करने के लिए असाधारण अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने का वारंट देगा।

(39) हालाँकि, इस क्षेत्राधिकार के भीतर निस्संदेह एकल बैंच के फैसले हैं जहां तलाशी वारंट को रद्द करने की ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो पुनरीक्षण या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत किया गया है। श्री थापर ने बहुत निष्पक्षता से स्वीकार किया कि पूर्ण बैंच के फैसले की रिपोर्ट की गई है आयकर अधिकारी जुलुंदुर बनाम राज्य (18) के रूप में, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि माना जाता है कि तलाशी वारंट निष्पादित नहीं किया गया था और सभी न्यायालयों में शुरू से ही स्थगन का आदेश था। इसी प्रकार, मेजर अवतार सिंह बनाम राज्य और अन्य, (19) के तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उस मामले में तलाशी वारंट भी निष्पादित नहीं किया गया था और न्यायालय मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी सामग्री नहीं थी। जिससे वह सामान्य तलाशी वारंट जारी करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो सके और उसने इसके तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया था। इसलिए, ये मामले वर्तमान मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं

(40) शिव दयाल बनाम सोहन लाल बासर, (20)के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में, इस मामले पर तीन सर्च वारंट जारी करने के संदर्भ में विचार किया गया था, लेकिन निर्णय यह नहीं दर्शाता है कि इनमें से सभी या किसी को निष्पादित किया गया था या नहीं। दूसरी ओर चर्चा की प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त तलाशी वारंट पर प्रारंभिक चरण में ही रोक लगा दी गई थी और उन्होंने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में मामले को उच्च न्यायालय में भेजने की सिफारिश की थी। इसलिए, यह निर्णय अलग है, लेकिन फिर भी इसमें इस आशय की टिप्पणियाँ हैं कि तलाशी वारंट जारी करने से पहले कारणों को दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसा करने में विफलता से यह निष्कर्ष निकलेगा कि विवेक का प्रयोग मनमाना किया गया था और इसलिए यह आदेश को रद्द करने का एक अच्छा आधार होगा। सम्मान के साथ, मैं ऊपर दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के कारण तर्क की इस पंक्ति से सहमत होने में असमर्थ हूं और इसलिए, इस विशिष्ट बिंदु पर इसे खारिज कर दूंगा। श्री हरबंस सिंह, पूर्व अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पंजाब राज्य आदि (21) मामले में, स्पष्ट रूप से निष्पादित सर्च वारंट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द कर दिया गया था। सबसे पहले यह उजागर करना आवश्यक है कि इस मामले में तलाशी वारंट पूर्व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 96 के तहत जारी किया गया था जिसमें वर्तमान संहिता की धारा 397(2) के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं था जो अंतर्वर्ती आदेशों के मामले में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक लगाता है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एक संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान सुरक्षित किया गया निष्पादित तलाशी वारंट एक अलग स्तर पर खड़ा है या नहीं, इस मुद्दे को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा न तो उठाया गया था और न ही दूर से ही विज्ञापित किया गया था। फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि यह मुद्दा बिल्कुल भी पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं था और सर्च वारंट को रद्द करने के लिए मुख्य रूप से शिव दयाल के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था। उपरोक्त कारणों को विस्तार से दर्ज किया गया है। मैं, सम्मान के साथ, एक विपरीत राय का हूँ और इसलिए, इस फैसले को खारिज कर दिया जाएगा।

(41) इस फैसले से अलग होने से पहले मैं प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाए गए अत्यंत निष्पक्ष रुख पर ध्यान दूंगा। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि मामलों में जांच अभी भी जारी है (जो इन याचिकाओं के लंबित होने से थोड़ा बाधित हुआ है) और याचिकाकर्ताओं को केवल तलाशी वारंट के आधार पर कुछ लेखों और दस्तावेजों के कब्जे से वंचित किया गया है। उन्होंने बार-बार यह पेशकश की है कि सभी मामलों में याचिकाकर्ता जांच एजेंसी को यह दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं कि मामले की जांच से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होने वाली कोई भी संपत्ति उन्हें वापस की जा सकती है और ऐसे अनुरोध पर अनुकूल तरीके से विचार किया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। हालाँकि, इन संबंधित आवेदनों में याचिकाकर्ताओं का रुख प्रतिष्ठित और अटल था कि वे संपत्ति की वापसी के लिए संबंधित प्राधिकारी का सहारा नहीं लेंगे और इसके बजाय उन्होंने पूरी कार्यवाही को शुरू से ही रद्द करने का दावा किया। आशा है कि इस याचिका की अस्वीकृति किसी भी तरह से प्रतिवादी राज्य की ओर से अपनाए गए रुख में बदलाव नहीं करेगी यदि याचिकाकर्ता इसके बाद इस मामले में उनसे संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि-

(i) किसी संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान प्राप्त संहिता की धारा 93 के तहत आक्षेपित तलाशी वारंट निष्पादित कर दिए गए हैं और न्यायालय में वापस कर दिए गए हैं, और इस प्रकार समाप्त हो गए हैं। इसलिए ऐसी तलाशी और जब्ती को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं प्रकृति में निरर्थक और वस्तुतः निरर्थक हैं;

(ii) तलाशी वारंट जारी करने का निर्देश देने वाले विवादित आदेशों में कोई कानूनी या तथ्यात्मक कमजोरी नहीं है। ये वैध न्यायिक आदेश होने के नाते वास्तव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने से बहुत दूर हैं, जो संभवतः ऐसे आदेशों को रद्द करने के लिए असाधारण अंतर्निहित को लागू करने का वारंट दे सकता है जो अनिवार्य रूप से अंतर्वर्ती प्रकृति के हैं।

(42) परिणाम में 1977 के सभी चार आपराधिक विविध आवेदन संख्या 5500-एम, 5093-एम, 4739-एम, और 5836-एम को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रामनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा